आरक्षित

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

आदेश से अपील संख्या 440 / 2008

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड और एक अन्य

..... अपीलकर्ता

बनाम

महमूद हसन .....प्रत्यर्थी

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित सहरिया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पूरन सिंह रावत।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी,

यह अपील नई टिहरी में जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल की अदालत द्वारा 2007 के सिविल केस नंबर 15, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी और एक अन्य वी महमूद हसन में पारित 15.05.2008 के फैसले और आदेश के खिलाफ है। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (संक्षेप में, ''अधिनियम'') के तहत एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए 07.04.2007 के मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है और मध्यस्थ निर्णय को बरकरार रखा गया है।

2. मामले के निस्तारण के लिए आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, टिहरी जल विकास निगम (''टीएचडीसी'' जिसे बाद में ''अपीलकर्ता'' के रूप में संदर्भित किया जाता है) भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका गठन टिहरी बांध के निर्माण की मेगा परियोजना को निष्पादित करने के लिए किया गया था। बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप, विशाल क्षेत्र जलमग्न होना था। प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाना था। पुनर्वास का कार्य अपीलकर्ता द्वारा किया जाना था। विभिन्न स्थलों पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 110 घरों के निर्माण के लिए, अपीलकर्ता द्वारा निविदाएं जारी की गई थीं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत निविदा को स्वीकार कर लिया गया था। 16.10.1995 को, अपीलकर्ता और प्रतिवादी (''अनुबंध समझौता'') के बीच एक अनुबंध समझौता निष्पादित किया गया था। यह कार्य 12–09–1996 को या उससे पहले पूरा किया जाना था। अनुबंध के सार के रूप में काम पूरा होने की अवधि का उल्लेख किया गया था। समझौते की तारीख से ही काम शुरू होना था। कार्य का कुल मूल्य 59,84,735.43 रुपये था।

3. दस्तावेज से ज्ञात होता है कि अनुबंध समझौते के निष्पादन के बाद, विस्थापित व्यक्तियों ने 3 के बजाय नकद में मुआवजे का विकल्प चुना समझौते के तहत घरों का निर्माण किया जाएगा। इसलिए इस मामले को केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया था। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसने नवम्बर, 1997 में अपनी सिफारिशें दी थीं। यह सिफारिश की गई थी कि मकान बनाने के बजाय विस्थापित लोगों को नकद मुआवजा दिया जाए। यही कारण है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों के निर्माण की आवश्यकता अब आवश्यक महसूस नहीं की गई थी। इस बीच, पुनर्वास कार्य उत्तर प्रदेश राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 02–01–2001 को जारी एक पत्र द्वारा पुनर्वास का कार्य उत्तराखंड राज्य को सौंप दिया गया था। दिनांक 30–05–2003 को उत्तराखंड राज्य ने यह निर्णय लिया कि विचाराधीन करार के अंतर्गत कार्य का पर्यवेक्षण अपीलकर्ता द्वारा किया जाना था।

4. दिनांक 07.02.2001 को अधिशासी अभियंता, टिहरी बांध, ब्लॉक 22 ने सहायक अभियंता को पत्र लिखकर तथ्यों का खुलासा किया कि 110 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकानों का निर्माण क्यों नहीं किया जा सका और यहां तक कि 12 अन्य आवासों का निर्माण भी क्यों नहीं किया जा सका। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि शुरू में जब 110 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों का निर्माण नहीं किया जा सका, तो एक निर्णय लिया गया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों के बजाय, उत्तरदाता से कुछ अन्य काम किए जा सकते हैं, लेकिन वह भी पूरा नहीं किया जा सका)। इस पत्र के अनुसार, प्रबंधक (शहरी पुनर्वास) टीएचडीसी द्वारा अनुमोदित, अधूरा काम ठेकेदार से पूरा किया जा सकता है। और इसके अलावा, अनुबंध के कुल मूल्य के 5% की दर से ठेकेदार को मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से विभाग को बचाने के लिए, उसे 9–बी विस्तार स्थल (गीता भवन के पास) पर आठ टाइप –III घरों के निर्माण का काम सौंपा जाए। यह काम भी पूरा नहीं हुआ।

5. इसके बाद, अनुबंध और प्रतिवादी को किए जाने वाले भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी ने 12–09–2003 को एक नोटिस दिया और 14–08–2004 को एक अन्य नोटिस जारी किया जिसमें अपीलकर्ता को मध्यस्थता खंड लागू करने की आवश्यकता थी। इसके बाद, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत इस न्यायालय के समक्ष आया। इस न्यायालय में, मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त हो गई थी और 07.04. 2007 को मध्यस्थ निर्णय प्रदान किया गया था। यह वह अधिनिर्णय है, जिसे मामले में अधिनियम की धारा 34 के तहत असफल रूप से चुनौती दी गई थी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता अपील में है।

6. बहस की सराहना करने से पहले, यह बताना उचित होगा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी द्वारा क्या दावा किया गया था। प्रतिवादी ने निम्नलिखित शीर्षों के तहत सात दावे किए:

> ''(1) साइट की अनुपलब्धता के कारण दावे के रूप में देय भुगतान।

(2) सामग्री की हानि के कारण दावे के रूप में देय भुगतान जिसका उपयोग भवन के निर्माण के लिए नहीं किया जा सका था, लेकिन उसी के निर्माण के लिए एकत्र किया गया था।

(3) मोबिलाइजेशन एडवांस पर प्रभारित ब्याज की वापसी के कारण दावे के रूप में देय भुगतान।

(4) पूरा होने में विलंब के कारण दावे के रूप में देय भुगतान।

(5) किए गए कार्य के कारण दावे के रूप में देय भुगतान लेकिन भुगतान नहीं किया गया।

(6) कार्य पूरा न होने और उस कारण हुई हानि के कारण दावे के रूप में देय भुगतान।

(7) नियोक्ता की ओर से संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के माध्यम से मानसिक यातना उत्पीड़न और नुकसान के कारण दावे के रूप में देय भुगतान।

7. अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदक द्वारा दायर आवेदन पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान प्रस्तुत किया गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निपटान के लिए छह विवाद्यक तैयार किए। वे निम्नानुसार हैं: ''

1. किए गए कार्य के लिए ठेकेदार को देय और देय राशि क्या थी?

(प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे 5 को कवर करता है।)

2. मानसिक यातना, उत्पीड़न आदि के लिए ठेकेदार को देय राशि क्या हो सकती है?

(इसमें प्रतिवादी द्वारा किया गया दावा संख्या 7 शामिल है।)

3. अनुबंध के अनुसार प्रतिवादी (टीएचडीसी) की ओर से विफलता के कारण ठेकेदार को कितना नुकसान हो सकता है?

(इसमें प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 शामिल हैं।)

4. क्या ठेकेदार द्वारा किए गए दावे को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया है?

5. क्या प्रतिवादी प्रस्तुत प्रति दावा का हकदार है?

(प्रतिदावा को खारिज कर दिया गया है।)

6. क्या अनुबंध अधिनियम की धारा 56 द्वारा परिकल्पित पार्टियों के बीच अनुबंध की निराशा थी?

8. निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा किए गए सात प्रमुखों में से प्रत्येक के तहत क्या दावा किया गया था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा क्या अनुमति दी गई थी।

क्रम संख्या	दावा	मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय
1	साइट की अनुपलब्धता के कारण दावे के रूप में देय भुगतान । कुल 1,12,548.66 रुपये का दावा किया गया है।	अनुज्ञात नहीं की गई।
2	सामग्री की हानि के कारण दावे के रूप में देय भुगतान जिसका उपयोग भवन के निर्माण के लिए नहीं किया जा सका था, लेकिन उसी के निर्माण के लिए एकत्र किया गया था। कुल दावा रु. 10,00,000/–	रु. 2,25,000/–
3	मेबिलाइजेशन एडवांस पर लिए गए ब्याज की वापसी के दावे के रूप में देय भुगतान।	रू0 10,000/– अनुज्ञात की गई है।
4	पूरा होने में देरी के कारण दावे के रूप में देय भुगतान। कुल दावा रू0 8,28,343	अनुज्ञात की गई।
5	किए गए लेकिन भुगतान नहीं किए गए कार्य के कारण दावे के रूप में देय भुगतान। कुल	रू0 8,84,614/–

	दावा रू0 10,32,775/–	
6	कार्य पूरा न होने के कारण दावे के रूप में देय भुगतान और उस खाते में नुकसान हुआ। कुल दावा रू0 14,88,380/–	रू0 2,50,000/–
7	मानसिक यातना उत्पीड़न और नियोक्ता की ओर से संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के कारण हुए नुकसान के कारण दावे के रूप में देय भुगतान। कुल दावा रू0 1,00,000	अनुज्ञात नहीं है।

9. विवाद्यक संख्या 4 पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अवधारित किया गया है कि विवाद्यक संख्या 04 परिसीमा काल से बाधक नहीं है।

10. विवाद्यक संख्या 6 अनुबंध की हताशा के संबंध में है। मध्यस्थता अधिनिर्णय में, यह नोट किया गया है कि **''यह महसूस करते हुए कि याचिका कमजोर और कमजोर है, टीएचडीसी ने अपने वकील और विभागीय अधिकारी के माध्यम से इस मुद्दे पर सही तरीके से दबाव नहीं डाला, जिसे हटा दिया गया था''।** तदनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ इस मुद्दे पर फैसला किया गया है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और दस्तावेजों का अवलोकन किया।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगेः–

(i) मध्यस्थ अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है। यह अधिनिर्णय अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है।

(ii) दावों पर बिना किसी साक्ष्य के निर्णय लिया गया है।

(iii) तत्काल मामले में ब्याज नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि यह अनुबंध के निबंधन और शर्तों द्वारा प्रतिबंधित था।

(iv) अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दायर आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि अनुरूप नहीं है।

13. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि यह अपील अधिनियम की धारा 37 के तहत है। यह न्यायालय मध्यस्थ अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील में नहीं बैठ सकता। अधिनियम की धारा 37 के तहत क्षेत्राधिकार सीमित है। तथ्यात्मक पहलुओं की जांच नहीं की जा सकती। यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो इसे अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्यवाही में परेशान नहीं किया जा सकता है। ब्याज के प्रश्न पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने संविदा के खंड की सही व्याख्या की है और ब्याज दिया है।

14. यह अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील है। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (''UNCITRAL''), वर्ष 1985 में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर मॉडल कानून के अनुरूप अधिनियमित किया गया है। मध्यस्थता निर्णय में न्यायालय की देरी और हस्तक्षेप चिंता का कारण था।

15. अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, जो निम्नानुसार है :–

> **34.** मध्यस्थम अधिनिर्णय अपास्त करने के लिए आवेदन–
>
> (1) किसी मध्यस्थ अधिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को निरस्त करने के लिए आवेदन द्वारा किया जा सकता है।
>
> (2) एक मध्यस्थ निर्णय को अदालत द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब–
>
> (a) आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड के आधार पर स्थापित करता है कि–

(i) एक पार्टी कुछ अक्षमता के अधीन थी, या

(ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पार्टियों ने इसे किया है या, उस पर कोई संकेत नहीं देना, कुछ समय के लिए लागू कानून के तहतय या

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था या

(iv) मध्यस्थ निर्णय एक ऐसे विवाद से संबंधित है जिस पर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर विचार नहीं किया गया है या नहीं किया गया है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैंः बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस तरह प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो मध्यस्थ अधिनिर्णय का केवल वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को रद्द किया जा सकता है या

(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के एक प्रावधान के साथ संघर्ष में नहीं था, जिससे पार्टियां अलग नहीं हो सकती हैं, या, ऐसे समझौते को विफल करना, इस भाग के अनुसार नहीं था या

(b) न्यायालय ने पाया कि–

(i) विवाद की विषय–वस्तु मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत, या

(ii) मध्यस्थ अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है।

स्पष्टीकरण I- किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है, केवल तभी जब, –

(i) अधिनिर्णय का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन थाय नहीं तो

(ii) यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हैय नहीं तो

(iii) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष में है।

स्पष्टीकरण 2. – संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है, विवाद के गुण–दोष पर समीक्षा नहीं होगी।

(2क) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न मध्यस्थ निर्णय को भी अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि अदालत को लगता है कि निर्णय के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से गलत हैः बशर्ते कि किसी अधिनिर्णय को केवल कानून के गलत आवेदन के आधार पर या साक्ष्य की पुनर्निर्धारण द्वारा रद्द नहीं किया जाएगा।

(3) निरस्त करने के लिए आवेदन तब नहीं किया जा सकता है जब उस आवेदन को करने वाले पक्ष को मध्यस्थ अधिनिर्णय प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस तारीख को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्व ारा उस अनुरोध का निपटान किया गया थाः बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को पर्याप्त कारण से भीतर आवेदन करने से रोका गया था। तीन महीने की उक्त अवधि के लिए, यह तीस दिनों की एक और अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, जहां यह उचित है और किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किया गया है, उसके द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए कार्यवाही स्थगित कर सकता है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थ कार्यवाही को फिर से शुरू करने या मध्यस्थ की राय में ऐसी अन्य कार्रवाई करने का अवसर दिया जा सके। ट्रिब्यूनल मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के आधार को समाप्त कर देगा।

(5) इस धारा के अधीन आवेदन किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी करने के बाद ही दायर किया जाएगा और ऐसे आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त आवश्यकता के अनुपालन का समर्थन करते हुए एक हलफनामा भी होगा।

(6) इस धारा के अधीन आवेदन का निपटान शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा जिस तारीख को उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस दूसरे पक्ष को दिया जाता है।

16. अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) के स्पष्टीकरण को 23.10.2015 से 2016 के अधिनियम संख्या 03 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 23.10.2015 से पहले, धारा 34 (2) (बी) का स्पष्टीकरण निम्नानुसार थाः

उप–खंड (ii) की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह घोषित किया जाता है कि किसी भी संदेह से बचने के लिए, एक अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है यदि अधिनिर्णय का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), (2019) 15 एससीसी 131 मामले में इस संशोधन के प्रभाव पर विचार किया गया है।

''**34**. इसलिए, जो स्पष्ट है, वह यह है कि ''भारत की सार्वजनिक नीति'', चाहे धारा 34 में निहित हो या धारा 48 में निहित हो, का अर्थ अब ''भारतीय कानून की मौलिक नीति'' होगा, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स ख्एसोसिएट बिल्डर्स बनाम एसोसिएट बिल्डर्स बनाम, के पैरा 18 और 27 में समझाया गया है। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49 : (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, यानी भारतीय कानून की मौलिक नीति को ''रेणुसागर'' 14 तक सीमित कर दिया जाएगा इस अभिव्यक्ति

की समझ। इसका मतलब यह होगा कि पश्चिमी गेको [ओएनजीसी बनाम ओएनजीसी वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड , (2014) 9 एससीसी 263: (2014) 5 एससीसी (सीआईवी) 12, विस्तार को समाप्त

कर दिया गया है। संक्षेप में, पश्चिमी गेको [ओएनजीसी बनाम ओएनजीसी। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड , (2014) 9 एससीसी 263: (2014) 5 एससीसी (सीआईवी) 12,, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स

[एसोसिएट बिल्डर्स वी। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49 : (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, अब प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस आधार पर एक अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने की आड़ में कि मध्यस्थ ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, अदालत का हस्तक्षेप अधिनिर्णय के गुण–दोष पर होगा, जिसे संशोधन के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है। तथापि, जहां तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संबंध है, जैसा कि

1996 अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (क) (iii) में निहित है, ये एक अधिनिर्णय को चुनौती देने का आधार बने हुए हैं, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स ख्एसोसिएट बिल्डर्स बनाम एसोसिएट बिल्डर्स बनाम एसोसिएट बिल्डर्स वी, के पैरा 30 में निहित है। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, ।

35. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तक्षेप का आधार जहां तक ''भारत के हित'' से संबंधित है, तब से हटा दिया गया है, और इसलिए, अब प्राप्त नहीं होता है। समान रूप से, इस आधार पर हस्तक्षेप का आधार कि अधिनिर्णय न्याय या नैतिकता के साथ संघर्ष में है, अब ''नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं'' के साथ संघर्ष के रूप में समझा जाना चाहिए। यह फिर से एसोसिएट बिल्डर्स ख्एसोसिएट बिल्डर्स बनाम एसोसिएट बिल्डर्स वी, के पैरा 36 से 39 के अनुरूप होगा। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, क्योंकि यह केवल ऐसे मध्यस्थ अधिनिर्णय हैं जो अदालत की अंतरात्मा को झकझोरते हैं जिन्हें इस आधार पर खारिज किया जा सकता है।

36. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत की सार्वजनिक नीति का अर्थ अब सबसे पहले यह है कि एक घरेलू अधिनिर्णय भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स ख्एसोसिएट बिल्डर्स बनाम एसोसिएट बिल्डर्स बनाम, के पैरा 18 और 27 में समझा

गया है। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, या दूसरी बात, कि इस तरह का अधिनिर्णय न्याय या नैतिकता की बुनियादी धारणाओं के खिलाफ है जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स ख्एसोसिएट बिल्डर्स बनाम एसोसिएट बिल्डर्स वी, के पैरा 36 से 39 में समझा गया है। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2

एससीसी (सीआईवी) 204, । धारा 34 (2) (बी) (ii) के लिए स्पष्टीकरण 2 और धारा 48 (2) (बी) (पप) के स्पष्टीकरण 2 को संशोधन अधिनियम द्वारा केवल इसलिए जोड़ा गया था ताकि पश्चिमी जीको ख्ओएनजीसी बनाम ओएनजीसी बनाम ओएनजीसी बनाम वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड , (2014) 9 एससीसी 263: (2014) 5 एससीसी (सीआईवी) 12,, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स ख्एसोसिएट बिल्डर्स वी। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, और विशेष रूप से पैरा 28 और 29 को अब हटा दिया गया है।

37. जहां तक भारत में किए गए घरेलू अधिनिर्णयों का संबंध है, संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 34 में जोड़ी गई उप–धारा (2–ए) के तहत अब एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध है। यहां, अधिनिर्णय के चेहरे पर स्पष्ट अवैधता दिखाई देनी चाहिए, जो इस तरह की अवैधता को संदर्भित करती है जो मामले की जड़ तक जाती है लेकिन जो केवल गलत नहीं है। कानून का अनुप्रयोग। संक्षेप में, जो चीज ''भारतीय कानून की मौलिक नीति'' में शामिल नहीं है, अर्थात्, एक कानून का उल्लंघन जो सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़ा नहीं है, को पिछले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है जब पेटेंट अवैधता के आधार पर एक अधिनिर्णय को अलग करने की बात आती है।

38. दूसरी बात, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य की पुनः समीक्षा, जो कि एक अपीलीय न्यायालय को करने की अनुमति है, को इस आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह निर्णय के चेहरे पर प्रकट होने वाली पेटेंट अवैधता के आधार पर है।

39. एसोसिएट बिल्डर्स के पैरा 42.1 को स्पष्ट करने के लिए

[एसोसिएट बिल्डर्स बनाम एसोसिएट बिल्डर्स। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49 : (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, अर्थात भारत के मूल कानून का केवल उल्लंघन, अब मध्यस्थ निर्णय को अलग करने के लिए उपलब्ध आधार नहीं है। एसोसिएट बिल्डर्स का पैरा 42.2

[एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, हालांकि, बना रहेगा, क्योंकि यदि कोई मध्यस्थ किसी अधिनिर्णय के लिए कोई कारण नहीं देता है और 1996 अधिनियम की धारा 31 (3) का उल्लंघन करता है, तो यह निश्चित रूप से अधिनिर्णय के लिए एक पेटेंट अवैधता होगी।

18. रेणुसागर पावर कंपनी लिमिटेड जनरल इलेक्ट्रिक कं, 1994 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशी अधिनिर्णय (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 की धारा 7 (1) (बी) (ii) के संदर्भ में ''सार्वजनिक नीति'' शब्द की व्याख्या की। न्यायालय ने विदेशी मध्यस्थ अधिनिर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन (न्यूयॉर्क, 1958) के अनुच्छेद V (2) (इ), विदेशी मध्यस्थ अधिनिर्णयों के निष्पादन पर कन्वेंशन के अनुच्छेद I (e), 1927 के अनुच्छेद I (e) और मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937 की धारा 7 (1) में ''सार्वजनिक नीति'' शब्दों पर विचार किया। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा **''उक्त मानदंडों को लागू करते हुए यह माना जाना चाहिए कि 16 का प्रवर्तन विदेशी अधिनिर्णय को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा कि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत है यदि इस तरह का प्रवर्तन (i) भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत होगा; या (ii) भारत के हित; या (iii) न्याय या नैतिकता।**

19. रेणुसागर (उक्त) के मामले में ''सार्वजनिक नीति'' शब्दों को दी गई व्याख्या पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम

लिमिटेड बनाम साव पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी 705 के मामले में आगे विचार किया गया है। सॉ पाइप्स (उक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ''भारत की सार्वजनिक नीति'' वाक्यांश को व्यापक अर्थ दिया। निर्णय के पैरा 31 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है –

> **31.** इसलिए, हमारे विचार में, संदर्भ में धारा 34 में उपयोग किए गए वाक्यांश ''भारत की सार्वजनिक नीति'' को व्यापक अर्थ दिया जाना आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक नीति की अवधारणा कुछ ऐसे मामलों को दर्शाती है जो सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित हैं। जो सार्वजनिक भलाई के लिए है या सार्वजनिक हित में है या जो सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक या हानिकारक होगा, वह समय–समय पर भिन्न होता रहा है। तथापि, जो निर्णय सांविधिक उपबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है, उसे जनहित में नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के निर्णय से न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए, हमारे विचार में रेणुसागर मामले [1994 सप्ली (1) एससीसी 644, में ''सार्वजनिक नीति'' शब्द को दिए गए संकीर्ण अर्थ के अलावा यह माना जाना आवश्यक है कि अधिनिर्णय को रद्द किया जा सकता है यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है। इसका परिणाम यह होगा कि यदि यह भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत है तो इसे रद्द किया जा सकता हैय या (ख) भारत का हितय या 17(ग) न्याय या नैतिकता, या (घ) इसके अतिरिक्त, यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है। अवैधता को मामले की जड़ तक जाना चाहिए और यदि अवैधता तुच्छ प्रकृति की है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनिर्णय सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। अधिनिर्णय को रद्द भी किया जा सकता है यदि यह इतना अनुचित और अनुचित है कि यह अदालत की अंतरात्मा को झटका देता है। इस तरह का अधिनिर्णय सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इसे शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है।

20. दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम आरएस शर्मा एंड कंपनी, नई दिल्ली, (2008) 13 एससीसी 80 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 21 में कानून को संक्षेप में प्रस्तुत कियाः

> 21. उपर्युक्त निर्णयों से, निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैंः

(अ) एक अधिनिर्णय, जो कि

(i) कानून के मूल प्रावधानों के विपरीत है

(ii) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानय या

(ii) संबंधित अनुबंध की शर्तों के खिलाफय या

(iv) स्पष्ट रूप से अवैधय या

(v) पार्टियों के अधिकारों के लिए पूर्वाग्रहपूर्णय अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अदालत द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला है।

(ब) अधिनिर्णय को रद्द किया जा सकता है यदि यह निम्नलिखित के विपरीत हैः

(क) भारतीय कानून की मौलिक नीति या

(ख) भारत का हित या

(ग) न्याय या नैतिकता।

(घ) यदि यह इतना अनुचित और अयुक्त है कि यह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है तो इस निर्णय को रद्द भी किया जा सकता है।

(ड.) न्यायालय के पास यह विचार करने का विकल्प है कि क्या यह आदेश संविदा की विशिष्ट शर्तों के विरुद्ध है और यदि हां, तो इस आधार पर इसमें हस्तक्षेप करें कि यह स्पष्ट रूप से अवैध है और भारत की सार्वजनिक नीति का विरोध करता है।

21. किसी अधिनिर्णय को कैसे पढ़ा जाए, अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर विचार करते समय और क्या देखने की आवश्यकता है, इसमें 18 है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 263 के मामले में भी चर्चा की गई है। पश्चिमी गेको (उक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार के लिए तीन और कारक जोड़े। वे हैं – (i) न्यायिक दृष्टिकोण (ii) प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत और (iii) एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम वेडनेसबरी कॉर्पन, (1948) 1 केबी 223: 1947 (2) ऑल ईआर

680 (सीए) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों की कसौटी पर तर्कसंगतता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः–

> ''**35.** प्रश्न यह है कि तब ''भारतीय कानून की मौलिक नीति'' क्या होगी। ओएनजीसी [ओएनजीसी लिमिटेड बनाम साव पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी 705, में निर्णय उस पहलू को विस्तृत नहीं करता है। फिर भी, अभिव्यक्ति में, हमारी राय में, इस देश में न्याय के प्रशासन और कानून के प्रवर्तन के लिए आधार प्रदान करने जैसे सभी मौलिक सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए। ''भारतीय कानून की मौलिक नीति'' अभिव्यक्ति के उद्देश्य को व्यापक रूप से गिनने के अर्थ के बिना, हम तीन अलग–अलग और मौलिक न्यायिक सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें आवश्यक रूप से भारतीय कानून की मौलिक नीति के एक हिस्से और पार्सल के रूप में समझा जाना चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर निर्धारण में चाहे अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा जो किसी नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करता है या किसी भी नागरिक परिणाम की ओर जाता है, संबंधित अदालत या प्राधिकरण उस मामले में ''न्यायिक दृष्टिकोण'' को अपनाने के लिए बाध्य है जिसे कानूनी बोलचाल में ''न्यायिक दृष्टिकोण'' कहा जाता है। न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने का कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति से उत्पन्न होता है या प्राधिकरण को संबंधित के लिए अलग से या अतिरिक्त रूप से संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। याद रखने वाली बात यह है कि न्यायिक और अर्ध–न्यायिक निर्धारण में न्यायिक दृष्टिकोण का महत्व इस तथ्य में निहित है कि जब तक अदालत, न्यायाधिकरण या अधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो उनके समक्ष पार्टियों के अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित करते हैं न्यायिक दृष्टिकोण के प्रति निष्ठा दिखाता है, वे मनमाने, मनमौजी या सनकी तरीके से कार्य नहीं कर सकते। न्यायिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकरण सही तरीके से कार्य करता है और निष्पक्ष, उचित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से विषय से निपटता है और यह कि इसका निर्णय किसी भी बाहरी विचार से कार्य नहीं करता है। उस अर्थ में न्यायिक दृष्टिकोण खामियों और दोषों के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करता है जो अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के फैसले को चुनौती के लिए असुरक्षित बना सकते हैं।
>
> **38.** भारतीय कानून की नीति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और वास्तव में मौलिक सिद्धांत यह है कि एक अदालत और इसलिए एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण

को भी, अपने समक्ष पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करते समय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पहलुओं में से एक यह है कि मामले का निर्णय लेने वाले न्यायालय /प्राधिकरण को किसी न किसी तरह से विचार करते समय परिचर तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। मन का उपयोग न करना एक दोष है जो किसी भी निर्णय के लिए घातक है। मन का अनुप्रयोग मन के प्रकटीकरण द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शित किया जाता है और मन का प्रकटीकरण उस निर्णय के समर्थन में कारणों को रिकॉर्ड करके किया जाता है जो अदालत या प्राधिकरण ले रहा है। यह आवश्यकता कि एक न्यायिक प्राधिकारी को अपने दिमाग को लागू करना चाहिए, उस दृष्टिकोण में, हमारे न्यायशास्त्र में इतनी गहराई से अंतर्निहित है कि इसे भारतीय कानून की मौलिक नीति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

39. प्रशासनिक कानून में अब यह सिद्धांत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि एक निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंच सकता है, कानून की अदालत में कायम नहीं रहेगा। निर्णयों की विकृति या तर्कहीनता का परीक्षण वेडेन्सबरी सिद्धांत [एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज लिमिटेड बनाम वेडनेसबरी कॉर्पन, (1948) 1 केबी 223: (1947) 2 ऑल ईआर 680 (सीए), की कसौटी पर किया जाता है। तर्कसंगतता के मानकों से कम आने वाले निर्णय अक्सर उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र में कानून की अदालत में चुनौती देने के लिए खुले होते हैं, लेकिन वैधानिक प्रक्रियाओं में कम नहीं होते हैं जहां भी वे उपलब्ध होते हैं।

22. एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2015) 3 एससीसी 49 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ''न्यायिक दृष्टिकोण'' ''प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत'' तथा ''तर्कसंगतता'' वाक्यांशों की व्याख्या इस प्रकार की है।

29. यह स्पष्ट है कि ''न्यायिक दृष्टिकोण'' का न्यायिक सिद्धांत यह मांग करता है कि एक निर्णय निष्पक्ष, उचित और उद्देश्यपूर्ण हो। सामने की तरफ, कुछ भी मनमाना और सनकी स्पष्ट रूप से एक निर्धारण नहीं होगा जो या तो उचित, उचित या उद्देश्यपूर्ण होगा। **30.** ऑडी अल्टरनेटम पार्टम सिद्धांत जो निस्संदेह

भारतीय कानून में एक मौलिक न्यायिक सिद्धांत है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में भी निहित है। ये धाराएं इस प्रकार हैं:

''18. पार्टियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा– पार्टियों के साथ समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।

34. मध्यस्थ अधिनिर्णय को निरस्त करने के लिए आवेदन–(1)***

(2) न्यायालय द्वारा मध्यस्थ अधिनिर्णय को केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब– (क) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करे कि–''

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था;

31. तीसरा न्यायिक सिद्धांत यह है कि एक निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंच सकता है, महत्वपूर्ण है और कुछ हद तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह स्थापित कानून है कि जहां:

(i) एक निष्कर्ष बिना किसी सबूत पर आधारित है, या

(ii) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस निर्णय के लिए अप्रासंगिक किसी चीज को ध्यान में रखता है जिस पर वह आता है या

(iii) अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी करता है, ऐसा निर्णय आवश्यक रूप से विकृत होगा।

34. इस बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ कि दो मौलिक सिद्धांत जो भारतीय कानून की मौलिक नीति का हिस्सा हैं (कि मध्यस्थ के पास न्यायिक दृष्टिकोण होना चाहिए और उसे विकृत रूप से कार्य नहीं करना चाहिए) को समझा जाना चाहिए।

23. एसोसिएट बिल्डर्स (उक्त) के मामले में भी यह माना गया है कि जब अदालत 21 लागू करती है एक मध्यस्थ अधिनिर्णय में ''सार्वजनिक नीति परीक्षण'', यह अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है और परिणामस्वरूप तथ्य की त्रुटियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। यह देखा गया कि **''तथ्यों पर मध्यस्थ द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण को आवश्यक रूप से पारित करना होगा क्योंकि मध्यस्थ साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता का अंतिम स्वामी होता है जिस पर भरोसा किया जाता है जब वह अपना मध्यस्थ अधिनिर्णय देता है। इस प्रकार कम सबूतों या सबूतों के आधार पर एक अधिनिर्णय जो एक प्रशिक्षित कानूनी दिमाग के लिए गुणवत्ता में मापता नहीं है, इस स्कोर पर अमान्य नहीं माना जाएगा। एक बार जब यह पाया जाता है कि मध्यस्थों का दृष्टिकोण मनमाना या मनमौजी नहीं है, तो वह तथ्यों पर अंतिम शब्द है।**

24. अपीलकर्ता की ओर से एक तर्क दिया गया है कि चूंकि अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में दावों की अनुमति दी गई है, इसलिए मध्यस्थ अधिनिर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है और इसलिए, मध्यस्थ अधिनिर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

25. निस्संदेह, पेटेंट अवैधता एक अधिनिर्णय को अलग रखने के आधारों में से एक है। एसोसिएट बिल्डर्स (उक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पेटेंट अवैधता के सिद्धांत के तहत उप–प्रमुखों पर चर्चा की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> ''42. 1996 के अधिनियम में, इस सिद्धांत को ''पेटेंट अवैधता'' सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें बदले में, तीन उपशीर्षक शामिल हैं:

42.1 (क) भारत के मूल कानून का उल्लंघन करने पर मध्यस्थ अधिनिर्णय की मृत्यु हो जाएगी। इसे इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि इस तरह की अवैधता मामले की जड़ तक जानी चाहिए और तुच्छ प्रकृति की नहीं हो सकती है। यह वास्तव में अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) का उल्लंघन है, जो निम्नानुसार हैः

''28. विवाद के सार पर लागू नियम। (1) जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है –

(क) एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण भारत में कुछ समय के लिए लागू मूल कानून के अनुसार मध्यस्थता में प्रस्तुत विवाद का फैसला करेगा;

42.2. (ख) मध्यस्थता अधिनियम के उल्लंघन को ही पेटेंट अवैधता के रूप में माना जाएगा – उदाहरण के लिए यदि कोई मध्यस्थ अधिनियम की धारा 31 (3) के उल्लंघन में किसी निर्णय के लिए कोई कारण नहीं देता है, तो ऐसा निर्णय रद्द कर दिया जाएगा।

42.3. (ग) समान रूप से, पेटेंट अवैधता का तीसरा उपशीर्षक वास्तव में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (3) का उल्लंघन है, जिसमें अभिलिखित हैः

''28. विवाद के सार पर लागू नियम।–(1)– (2)***

(3) इस अंतिम उल्लंघन को एक चेतावनी के साथ समझा जाना चाहिए। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि एक मध्यस्थ उचित तरीके से अनुबंध की अवधि का निर्माण करता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस आधार पर अधिनिर्णय को अलग रखा जा सकता है। अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करने के लिए है जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं मानता है कि इसे कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं कर सकता है।

43. मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ख्मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एससीसी 181, में, इस अदालत ने निम्नानुसार मानाः (एससीसी पीपी 225–26, पैरा 112–13)

''**112.** यह स्पष्ट है कि अनुबंध की शर्तों को व्यक्त या निहित किया जा सकता है। पार्टियों का आचरण भी 23 होगा एक अनुबंध के निर्माण के मामले में एक प्रासंगिक कारक। अनुबंध समझौते का निर्माण मध्यस्थता समझौते की व्यापक प्रकृति, दायरे और दायरे को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थों के अधिकार क्षेत्र में है और उन्हें पार्टियों के आचरण को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित नहीं कहा जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से पार्टियों द्वारा आदान–प्रदान किए गए पत्राचार को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। एक अनुबंध की व्याख्या मध्यस्थ के लिए निर्धारित करने का मामला है, भले ही यह कानून के प्रश्न के निर्धारण को जन्म देता हो। [देखें प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग [(2003) 8 एससीसी 593: 2003 सुप्प (4) एससीआर 561, और डीडी शर्मा बनाम भारत संघ [(2004) 5 एससीसी 325,

113. एक बार, इस प्रकार, यह माना जाता है कि मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में था, कोई और प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि अधिनिर्णय के चेहरे पर कोई रोक मौजूद है।

.....

.....

.....''

26. एसोसिएट बिल्डर्स (उक्त) के फैसले में पैराग्राफ 42.3 पेटेंट अवैधता के तीसरे उप–प्रमुख से संबंधित है। यह उस स्थिति से संबंधित है जब मध्यस्थ अधिनिर्णय अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो कुछ कहा गया है, उसे दोहराने की आवश्यकता है। अदालत पुनरावृत्ति की कीमत पर इसे दोहराती है। यह देखा गया है कि **''एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई मध्यस्थ उचित तरीके से अनुबंध की अवधि का अर्थ लगाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस आधार पर अधिनिर्णय को रद्द कर दिया जा सकता है। 24 की शर्तों का निर्माण एक अनुबंध मुख्य रूप**

से एक मध्यस्थ के लिए तय करने के लिए है जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं मानता है कि इसे कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं कर सकता है।

27. रेणुसागर (उक्त), साव पाइप्स (उक्त), वेस्टर्न गेको (उक्त) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (उक्त) के मामले में दिए गए वाक्यांश ''सार्वजनिक नीति'' की व्याख्या अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) के स्पष्टीकरण में संशोधन से पहले दी गई थी। प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में, संशोधित प्रावधान जो आज मौजूद हैं, लागू होंगे या क्या वर्ष 2016 (23.10.2015 से) में किए गए संशोधन से पहले के प्रावधान लागू होंगे? इस विवाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2018) 6 एससीसी 287 के मामले में समाप्त कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''धारा 26 की योजना इस प्रकार स्पष्ट हैः कि संशोधन अधिनियम प्रकृति में भावी है, और उन मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू होगा जो 25 को प्रधान अधिनियम की धारा 21 द्वारा समझी गई हैं। या संशोधन अधिनियम के बाद, और अदालत की कार्यवाही जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या बाद में शुरू हुई है। ''।

28. इस मामले में, अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में मध्यस्थ कार्यवाही अधिनियम में संशोधन से पहले शुरू हुई थी और अधिनियम में संशोधन से पहले अदालत की कार्यवाही भी शुरू हुई थी। इसलिए, वर्ष 2016 (23.10.2015 से) में अधिनियम में शामिल संशोधन से पहले कानून के साथ तत्काल मामले को निपटाया जाएगा। तदनुसार, एसोसिएट बिल्डरों (उक्त) के मामले में सारांशित कानून मार्गदर्शक कारक होगा।

29. जहां तक अधिनियम की धारा 37 के तहत क्षेत्राधिकार का संबंध है, यह अधिनियम की धारा 34 के तहत लगाई गई सीमा से परे नहीं हो सकता है। एमएमटीसी लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड, (2019) 4 एससीसी 163 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस स्थिति को दोहराया गया है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र की सीमा पर माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले 26 में भी चर्चा की गई है। एमएमटीसी (उक्त) । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है

> **''11.** जहां तक धारा 34 का संबंध है, स्थिति अब तक अच्छी तरह से तय हो चुकी है कि न्यायालय मध्यस्थ अधिनिर्णय पर अपील में नहीं बैठता है और धारा 34 (2) (बी) (ii) के तहत प्रदान किए गए सीमित आधार पर गुण–दोष पर हस्तक्षेप कर सकता है यानी यदि निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। 2015 में 1996 के अधिनियम में संशोधन से पहले इस न्यायालय के फैसलों के माध्यम से स्पष्ट कानूनी स्थिति के अनुसार, भारतीय सार्वजनिक नीति का उल्लंघन, बदले में, भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन, भारत के हित का उल्लंघन, न्याय या नैतिकता के साथ संघर्ष, और मध्यस्थ अधिनिर्णय में पेटेंट अवैधता का अस्तित्व शामिल है। इसके अतिरिक्त, ''भारतीय कानून की मौलिक नीति'' की अवधारणा में कानूनों और न्यायिक मिसालों का अनुपालन, न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन, और वेडन्सबरी
>
> [एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस बनाम वेडेन्सबरी कॉर्पन, (1948) 1 केबी 223 (सीए), तर्कसंगतता शामिल होगी। इसके अलावा, ''पेटेंट अवैधता'' का अर्थ भारत के मूल कानून का उल्लंघन, 1996 के अधिनियम का उल्लंघन और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है। 12. यदि इनमें से किसी एक शर्त को पूरा किया जाता है, तो न्यायालय धारा 34 (2) (बी) (ii) के संदर्भ में मध्यस्थ निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप में विवाद के गुण–दोष की समीक्षा शामिल नहीं है, और यह उन स्थितियों तक सीमित है जहां मध्यस्थ के निष्कर्ष मनमाने, मनमौजी या विकृत हैं, या जब न्यायालय की अंतरात्मा को झटका लगता है, या जब अवैधता तुच्छ नहीं होती है, लेकिन मामले की जड़ तक जाती है। मध्यस्थ अधिनिर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथ्यों पर आधारित एक संभावित दृष्टिकोण है। (एसोसिएट
>
> बिल्डर्स बनाम डीडीए [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 204, देखें। ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स
>
> लिमिटेड [ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी 705, भी देखेंय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम फ्रेंड्स कोल कार्बोनाइजेशन

खहिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम फ्रेंड्स कोल कार्बोनाइजेशन, (2006) 4 एससीसी 445, य और मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ख्मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एससीसी 181,

14. जहां तक धारा 37 के अनुसार धारा 34 के तहत किए गए आदेश में हस्तक्षेप का सवाल है, यह विवादित नहीं हो सकता है कि धारा 37 के तहत इस तरह का हस्तक्षेप धारा 34 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों से आगे नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अदालत अधिनिर्णय के गुण–दोष का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर सकती है, और केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 27 के तहत अदालत द्वारा शक्ति का प्रयोग धारा 34 प्रावधान के दायरे से अधिक नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि धारा 34 के तहत अदालत द्वारा और धारा 37 के तहत अपील में अदालत द्वारा मध्यस्थ अधिनिर्णय की पुष्टि की गई है, तो इस अदालत को इस तरह के समवर्ती निष्कर्षों को परेशान करने के लिए बेहद सतर्क और धीमा होना चाहिए।

30. उपर्युक्त स्थापित सिद्धांत इस न्यायालय को तत्काल विवाद का निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करेगा। न्यायालय केवल इस स्तर पर एक और तथ्य पर ध्यान देना चाहता है, जो अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र के संबंध में है। अधिनियम की धारा 34 एक मध्यस्थ अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार करती है। प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय द्व ारा अधिनियम की धारा 34 या 37 के अधीन कार्यवाही में आंशिक संशोधन किया जा सकता है?

31. यह मुद्दा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 और 220 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एम हकीम और एक अन्य, (2021) 9 एससीसी 1 के मामले में चर्चा के लिए आया। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कानून पर विस्तार से चर्चा की, अधिनियम को अधिनियमित करने के विधायी इरादे पर विचार किया ताकि मध्यस्थ अधिनिर्णय में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः–

42. इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह प्रश्न अब 28 वर्ष की आयु में आखिरकार सुलझा लिया गया है कम से कम 3 निर्णय [मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक। अ. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड , (2006) 11 एससीसी 181, , [किन्नरी मलिक वी। घनश्याम दास दमानी, (2018) 11 एससीसी 328: (2018) 5 एससीसी (सीआईवी) 106,, ख्दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। अ. नेविगेंट टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड (2021) 7 एससीसी 657, इस न्यायालय का। अन्यथा भी, यह कहना कि न्यायिक प्रवृत्ति एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में प्रतीत होती है जो धारा 34 में पढ़कर अधिनिर्णय को संशोधित, संशोधित या भिन्न करने की शक्ति प्रदान करती है, 1940 के अधिनियम में निहित पिछले कानून की अनदेखी करना होगा इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया जाए कि 1996 का अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, 1985 पर यू एनसीआईटीएएल मॉडल कानून के आधार पर अधिनियमित किया गया था, जैसा कि रेडफर्न और हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में बताया गया है, यह स्पष्ट करता है कि, अत्यंत सीमित आधारों पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप को देखते हुए, जो किसी अधिनिर्णय के गुण–दोष से संबंधित नहीं है, धारा 34 के तहत ''सीमित उपाय'' ''सीमित अधिकार'' के साथ संगत है, अर्थात्, या तो एक फैसले को रद्द करना या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत मामले को रिमांड करना। '' (जोर दिया गया)

32. सभी सात दावों पर, जैसा कि ठेकेदार द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया है, प्रतिवादी के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि उन दावों पर मध्यस्थ निर्णय तथ्यों पर आधारित है, इसलिए, अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन सात दावों पर मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

33. अदालत सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ठेकेदार द्वारा किए गए सात दावों से निपटती है।

34. दावा संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 को मध्यस्थ अधिनिर्णय में मुद्दे संख्या 3 के तहत निपटाया गया है। दावा संख्या 1 **''साइट की अनुपलब्धता के कारण दावे के रूप में देय भुगतान''** के संबंध में है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस दावे की अनुमति नहीं दी, इसलिए इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

35. दावा संख्या 2 **''सामग्री के नुकसान के कारण दावे के रूप में देय भुगतान के संबंध में है जिसका उपयोग भवन के निर्माण के लिए नहीं किया जा सका, लेकिन उसी के निर्माण के लिए एकत्र किया गया था''।** ठेकेदार ने इस दावे के तहत 10 लाख रुपये का दावा किया और उसे 2,25,000 रुपये दिए गए।

36. अपीलकर्ता के वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि दावा अनुबंध खंड संख्या 15.2.08 की शर्तों के खिलाफ दिया गया है, जो ऐसी स्थिति के लिए क्षतिपूर्ति को रोकता है। यह खंड 15.02.08 कहता है कि ''मालिक द्वारा सामग्री जारी किए जाने के बाद ठेकेदार पूरी तरह से सामग्री की सुरक्षा, गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदार होगा''।

37. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि इस दावे पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर विचार किया गया है और तदनुसार, इसकी अनुमति दी गई है।

38. जैसा कि कहा गया है, तत्काल मामले में प्रतिवादी को पहले एक अनुबंध दिया गया था, लेकिन नीति में बदलाव के कारण काम पूरा नहीं किया जा सका। इसके बाद, उन्हें एक और काम दिया गया, लेकिन वह भी अधूरा रहा। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया कि अनुबंध में खंड का तत्काल तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कोई आवेदन नहीं है। यह कहा गया था कि **''यह सच है कि ठेकेदार को अपने हितों की रक्षा करनी थी और मौके पर दुकानों की देखभाल करनी थी, लेकिन यहां ठेकेदार को साइट उपलब्ध नहीं कराने और काम की प्रकृ**

ति और स्थान को बार–बार बदलने के कारण अपव्यय और हानि का सवाल है''।

39. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति के रूप में 2,25,000 रुपये दिए। निष्कर्ष को 31 की शर्तों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है ठेका। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध की शर्तों के खंड की व्याख्या की है और इसे तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत अलग किया है। इसलिए, दावे पर आपत्तियों को आक्षेपित निर्णय और आदेश में सही तरीके से खारिज कर दिया गया है। **40.** दावा संख्या 3 ''मोबिलाइजेशन एडवांस पर लगाए गए ब्याज की वापसी के कारण दावे के रूप में देय भुगतान'' के संबंध में है।

41. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि इस दावे को कैसे अनुमति दी गई है, इसका कोई कारण नहीं है। यह केवल एक अनुमान लगाने का काम है।

42. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की निम्नलिखित दलीलों पर ध्यान दिया कि **''इस तरह उक्त अग्रिम पर लगाए गए ब्याज की किसी भी राशि की वापसी का कोई सवाल ही नहीं है''।** यह माना गया था कि, वास्तव में, अपीलकर्ता ने मोबिलाइजेशन एडवांस पर ब्याज लगाया था। लामबंदी अग्रिम ब्याज मुक्त था। अपीलकर्ता ने इस तरह के विषय पर रखे गए किसी भी बिल या खातों या किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया। विचार करने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 32 द्वारा किए गए दावे के अनुसार 10,000 रुपये की राशि दी। ठेकेदार। आक्षेपित निर्णय और आदेश में, इस निष्कर्ष को बरकरार रखा गया है। अपील में, इस न्यायालय को कोई हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। यह सबूत का मामला है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय की अंतरात्मा को झटका नहीं देता है। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को आक्षेपित निर्णय और आदेश में सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

43. दावा संख्या 4 **''पूरा होने में देरी के कारण दावे के रूप में देय भुगतान''** के संबंध में है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया कि हर ठेकेदार लाभ पर काम करता है। अनुबंध का कार्य उसकी आजीविका का हिस्सा है। कुल काम का 15ः मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा इस मद के तहत दिया गया था। इस विषय पर कानून पर भी चर्चा की गई है। इस दावे की अनुमति देते समय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निष्कर्ष में कुछ भी गलत नहीं लगता है। इसके खिलाफ आपत्ति को आक्षेपित निर्णय और आदेश में सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

44. दावा संख्या 5 **''किए गए काम के कारण दावे के रूप में देय भुगतान के संबंध में है, लेकिन इसके लिए भुगतान नहीं किया गया है''।** यह दावा 33 में मुद्दा संख्या 1 के तहत कवर किया गया है मध्यस्थ अधिनिर्णय। प्रतिवादी ने 9,92,774.58 रुपये के साथ–साथ 40,000 रुपये की जमानत राशि का दावा किया। इस राशि के विरुद्ध कुल 8,84,614ध्– रुपये की अनुमति दी गई है।

45. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता पर गलत तरीके से भार डाला है। अपीलकर्ता ने गवाह को तलब करने की मांग की थी लेकिन अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था, जो प्रतिवादी के दावे को स्थापित कर सके। दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। इसका कोई आधार नहीं है।

46. प्रतिवादी की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि, वास्तव में, शुरू में प्रतिवादी को 110 ईडब्ल्यूएस घरों का निर्माण करने की आवश्यकता थी। उत्तरदाता ने 12 घरों का निर्माण किया, लेकिन नीति बदल दी गई। इसके बाद, प्रतिवादी को 8 टाइप –3 घरों का निर्माण करने के लिए कहा गया था। प्रतिवादी ने मैदान को समतल किया, पुरानी मौजूदा इमारतों को ध्वस्त कर दिया, सुरक्षा दीवार का निर्माण किया, लेकिन फिर से विभाग को प्रतिवादी को धर्मशाला बनाने की आवश्यकता थी। उन्हें चित्र प्रदान नहीं किए गए थे। जो

भी काम हुआ प्रतिवादी द्वारा, उसे इसके लिए भुगतान नहीं किया गया था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस राशि का सही भुगतान किया है।

47. वास्तव में, इस मामले में, अपीलकर्ता ने एक अलग रुख अपनाया है। अपीलकर्ता के अनुसार, वर्ष 1998 में, प्रतिवादी को उस काम के लिए भुगतान किया गया था जो उसने किया था। लेकिन, उत्तर प्रदेश राज्य को पुनर्वास कार्य के हस्तांतरण के बाद, प्रतिवादी को कुछ कार्य करने की आवश्यकता थी। उन्होंने इसके लिए भी भुगतान का दावा किया। ट्रिब्यूनल के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं किए गए। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने वास्तव में कहा, ''यह समझ में नहीं आता है कि टीएचडीसी ने इन मध्यस्थ कार्यवाही में दस्तावेज पेश करने में संकोच क्यों महसूस किया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विभाग और प्रतिवादी के बीच संचार को ध्यान में रखा।

48. प्रतिवादी ने उस कार्य का विवरण दिया है जो उसने किया है। यह बोझ डालने का प्रश्न नहीं है। प्रतिवादी ने माप और राशि दी है, जो उसने इस दावे के तहत निर्माण करने में खर्च की थी। अपीलकर्ता ने 35 दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि ऐसा काम नहीं किया गया था या दावा की गई राशि सही नहीं थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सही कहा है कि यदि पुनर्वास का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया था, तो वह अपीलकर्ता को अपने दायित्व से मुक्त नहीं करता है क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार भी, अपीलकर्ता अनुबंध के तहत उत्तरदायी है क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारी ने हमेशा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपीलकर्ता के एजेंट / प्रतिनिधियों के रूप में कार्य किया है। अपीलकर्ता ने कभी भी अनुबंध को रद्द या रद्द नहीं किया। एक तर्कसंगत आदेश द्वारा, इस दावे को अनुमति दी गई है। इस फैसले में इसे ठीक ही परेशान नहीं किया गया है।

49. दावा संख्या 6 **''काम पूरा नहीं होने और उस कारण हुए नुकसान के कारण दावे के रूप में देय भुगतान''** के संबंध में है।

50. इस दावे पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि अनुबंध के खंड 15 और 59 इस तरह के दावे पर रोक लगाते हैं। यह अधिनिर्णय संदर्भ से परे है, इसलिए, स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे केवल इस आधार पर अलग रखा जाना चाहिए।

51. मु0 8,28,343/– रुपये का दावा किया गया है, जो कि अनुज्ञात किया गया है। अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अनुबंध की शर्तों के खंड 33 में 5% क्षति का प्रावधान है। क्षति का दावा अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत किया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि दावा ठेकेदार द्वारा किए गए संचार के आधार पर दिया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, मध्यस्थ अधिनिर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे रद्द किया जा सकता है।

52. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे के विवरण पर विचार किया, जो अप्रयुक्त शटरिंग, अन्य उपकरणों और शिविर प्रतिष्ठान आदि पर मूल्यह्रास से संबंधित है। यह माना जाता है कि प्रतिवादी बिना किसी गलती के छह साल से अधिक समय तक काम से बंधा रहा। प्रतिवादी हमेशा तैयार था और अनुबंध कार्य करने के लिए तैयार था। ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है। यह न्यायालय, अपील की अदालत के रूप में, सावधानीपूर्वक जांच नहीं कर सकता है कि देय राशि कितनी है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस मद में 2,50,000 रुपये का आदेश दिया है। इस खोज में आक्षेपित निर्णय और आदेश में सही को परेशान नहीं किया गया था।

53. दावा संख्या 7 **''नियोक्ता की ओर से संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के कारण मानसिक यातना उत्पीड़न और नुकसान के कारण दावे के रूप में देय भुगतान''** के संबंध में है। इस दावे की अनुमति नहीं दी गई है।

54. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 31 (7) का संदर्भ देने वाले दावों पर ब्याज दिया है। अपीलकर्ता के वकील ने इस पर जोरदार आपत्ति जताई है। यह तर्क दिया जाता है कि ब्याज देना अनुबंध की शर्तों के खिलाफ है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुबंध के खंड 55.6.0 और 55.7.0 में ब्याज का भुगतान न करने का प्रावधान है। ये खंड निम्नानुसार हैं –

> **'55.6.0 विवाद आदि के कारण विलंबित भुगतान के लिए कोई दावा नहीं।** –ठेकेदार इस बात से सहमत है कि सरकार द्वारा किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा जो पार्टियों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण या तत्काल या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी इंजीनियर की ओर से किसी भी देरी या चूक के संबंध में या किसी अन्य संबंध में सरकार के पास पड़ा हो सकता है।
>
> 55.7.0. ठेकेदार को देय धन पर ब्याज। – माप पर देय राशि का भुगतान करने के लिए प्रभारी अभियंता की ओर से कोई चूक या अन्यथा अनुबंध को दूषित या शून्य नहीं करेगा, न ही ठेकेदार किसी गारंटी या 38 पर ब्याज का हकदार होगा।
>
> बकाया राशि का भुगतान और न ही किसी शेष राशि पर जो उसके खातों के अंतिम निपटान पर देय हो सकती है।

55. यह तर्क दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, (2012) 12 एससीसी 10 और (2019) 17 एससीसी 786 के मामले में इसी तरह के खंडों पर विचार किया गया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये खंड ब्याज देने की अनुमति नहीं देते हैं।

56. वर्ष 2012 के जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (उक्त) के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **''पार्टियों के बीच अनुबंध समझौते के उपरोक्त दो खंडों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दोनों खंडों द्वारा विचार की गई परिस्थितियों के कुछ ओवरलैपिंग के**

बावजूद, भुगतान में देरी के लिए ठेकेदार को कोई ब्याज देय नहीं है। या तो, अंतरिम या अंतिम, किए गए कार्यों के लिए या गारंटी के रूप में जमा में पड़ी किसी भी राशि पर। उपरोक्त विचारित परिणाम ऐसी स्थिति पर लागू होगा जहां भुगतान को रोकना किसी विवाद या पक्षों के बीच अंतर के कारण है या यहां तक कि अन्यथा भी।

57. वर्ष 2019 में जय प्रकाश (उक्त) के मामले में भी इसी तरह के खंड फिर से व्याख्या के लिए आए। दरअसल, जय प्रकाश (उक्त–2019) के मामले में हाईकोर्ट ने अनुबंध की शर्तों को देखते हुए ब्याज नहीं दिया था और इस आदेश को बरकरार रखा गया था।

58. दूसरी ओर, ठेकेदार के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संबंधित समय पर लागू कानून के मद्देनजर की गई थी और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने तदनुसार एक दृष्टिकोण लिया था। यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण ठोस न्यायिक तर्क पर आधारित हैय यह एक संभावित दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मध्यस्थ अधिनिर्णय को स्पष्ट रूप से अवैध बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में उन्हीं खंडों को ब्याज को प्रतिबंधित करने के रूप में रखा गया था। यह तर्क दिया जाता है कि यह मध्यस्थ अधिनिर्णय को बिल्कुल भी खराब नहीं करता है।

59. प्रस्तुत मामले में, अनुबंध खंड संख्या 55.6.0. और 55.7.0 में दिए गए अनुसार कुछ परिस्थितियों में इसके तहत ब्याज का भुगतान न करने का प्रावधान है। यह एक तथ्य है कि बाद में वर्ष 2012 और 2019 में, जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (उक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह के खंडों की व्याख्या की गई है और यह माना जाता है कि ये खंड ब्याज के भुगतान पर रोक लगाते हैं।

60. प्रश्न यह है कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (उक्त) के मामले में और आगे वर्ष 2019 में जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (उक्त) के मामले में दिए गए खंडों की व्याख्या तत्काल मामले में मध्यस्थ अधिनिर्णय पर लागू होगी जो वर्ष 2007 में दिया गया था ताकि यह माना जा सके कि मध्यस्थ अधिनिर्णय कानून के खिलाफ है।

61. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस मामले में ब्याज देते समय उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मेसर्स हरीश चंद एंड कंपनी (1999) (1) एससीसी 63 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार किया है। अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (7) में ब्याज के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह निम्नानुसार हैः ''31। मध्यस्थ अधिनिर्णय का रूप और सामग्री।(1)...

(2).....

(3).....

(4).....

(5).....

(6).....

(7) (क) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, जहां तक मध्यस्थ अधिनिर्णय धन के भुगतान के लिए है, मध्यस्थ अधिकरण उस राशि को शामिल कर सकेगा जिसके लिए अधिनिर्णय को ब्याज दिया जाता है, ऐसी दर पर, जो वह धन के सम्पूर्ण या किसी भाग पर, कार्रवाई उत्पन्न होने की तारीख और कार्रवाई के उत्पन्न होने की तारीख के बीच की अवधि के पूरे या किसी भाग के लिए उचित समझे। जिस तारीख को अधिनिर्णय दिया जाता है।

(ख) मध्यस्थ अधिनिर्णय द्वारा भुगतान की जाने वाली निदेशित राशि, जब तक कि अधिनिर्णय अन्यथा निदेश न दे, अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान की तारीख तक, अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से दो प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज वहन करेगा।

स्पष्टीकरण – ''ब्याज की वर्तमान दर'' का वही अर्थ होगा जो इसे ब्याज अधिनियम, 1978 (1978 का 14) की धारा 2 के खंड (बी) के तहत सौंपा गया है।''

62. धारा 31 की उपधारा (7) ब्याज के भुगतान के मामले में अनुबंध की अवधि की व्याख्या के लिए अधिदेशित करती है। हरीश चंद (सुप्रा) के मामले में, ब्याज के संबंध में निम्नलिखित खंड की व्याख्या की गई है –

> **''1.9 विवाद आदि के कारण विलंबित भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा –** ब्याज या क्षति के लिए सरकार द्वारा किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा जो किसी विवाद के कारण सरकार के पास पड़ा हो सकता है। अंतरय या समय–समय पर या अंतिम भुगतान या किसी अन्य संबंध में इंजीनियर–इन–चार्ज के बीच गलतफहमी।

63. हरीश चंद (उक्त) के मामले में फैसले के पैरा 10 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुबंध के खंड 1.9 की व्याख्या करते हुए, जैसा कि पहले उद्धृत किया गया था, कहा कि **''दावा किए गए कार्य के लिए क्षति या भुगतान के दावे के लिए और जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से किसी भी धन को कवर नहीं करेगा जिसे सरकार के पास पड़ा हुआ कहा जा सकता है। नतीजतन, इस खंड की स्पष्ट भाषा में, प्रतिवादी–ठेकेदार के खिलाफ कोई निषेध नहीं है कि वह निर्णय के लिए रखी गई प्रासंगिक वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष नुकसान के माध्यम से ब्याज के लिए दावा नहीं उठा सकता है।** ''

64. वास्तव में सईद अहमद एंड कंपनी बनाम इस मामले में हितों के निर्धारण के प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2009) 12 एससीसी 26, अनुबंध के निम्नलिखित खंड पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था–

> ''जी. 1.09. ब्याज या क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा जो सरकार के पास पड़ा हो या एक तरफ प्रभारी अभियंता और दूसरी ओर ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद, अंतर या गलतफहमी के कारण या समय–समय पर या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता की ओर से किसी भी देरी के संबंध में हो सकता है।

65. सईद अहमद (उक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 43 में निर्धारित कानून पर चर्चा की हरीश चंद (उक्त) के मामले में और कहा कि सईद के मामले में अनुबंध की शर्तें अनुबंध की शर्तों से अलग हैं जैसा कि हरीश चंद (उक्त) के मामले में निहित है। सईद (उक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> **''19.** लेकिन वर्तमान मामले में, खंड जी 1.09 काफी अलग है। इसमें विशेष रूप से प्रावधान है कि प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच किसी विवाद, अंतर या गलतफहमी के कारण या प्रभारी अभियंता की ओर से आवधिक या अंतिम भुगतान करने में या किसी अन्य संबंध के संबंध में किसी भी देरी के संबंध में किसी भी धन के संबंध में कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस मामले में खंड जी 1.09 के तहत बार पूर्ण होने के कारण, हरीश चंद्र [(1999) 1 एससीसी 63, में निर्णय अपीलकर्ता को किसी भी तरह से सहायता नहीं करेगा।

66. वर्ष 2019 के जय प्रकाश (उक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिंदु पर कानून पर चर्चा की। पैरा 18 और 19 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक प्रश्न पूछा और पैराग्राफ 20 में इसका उत्तर दिया। निर्णय के पैरा 18, 19 और 20 इस प्रकार हैं:

> **''18** उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण भी उतना ही विश्वसनीय है। जीसीसी के खंड 50 और 51 टीएचडीसी मामले खटिहरी

हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, में जीसीसी के खंड 1.2.14 और 1.2. 15 के साथ परीमेटेरिया हैं । अ. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड , (2012) 12 एससीसी 10 : (2013) 2 एससीसी (सीआईवी) 122, । उन खंडों की व्याख्या यह कहते हुए की गई है कि ठेकेदार को देय विलंबित भुगतान के दावे पर कोई ब्याज देय नहीं है। इन खंडों के संबंध में अपनाया गया वही निर्माण, जो वास्तव में, एक ही पक्ष के बीच का मामला है, बिना किसी दोष के है।

19. इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता का एकमात्र तर्क जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या इस तरह का निर्माण हरीश चंद्र मामले

[उत्तर प्रदेश राज्य, के फैसले के विपरीत है। अ. हरीश चंद्र एंड कंपनी। , (1999) 1 एससीसी 63, ।

20. इस तर्क का पूरा उत्तर रिलायंस सेल्यूलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड में दिया गया है। [रिलायंस सेल्यूलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अ. ओएनजीसी, (2018) 9 एससीसी 266: (2018) 4 एससीसी (सीआईवी) 351, निर्णय। निम्नलिखित चर्चा उसमें निहित थी जिसमें टीएचडीसी खटिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पर चर्चा की गई थी। अ. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (2012) 12 एससीसी 10 : (2013) 2 एससीसी (सीआईवी) 122, निर्णय यह प्रदर्शित करेगा: (रिलायंस सेल्यूलोज मामला खरिलायंस सेल्यूलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड,। अ. ओएनजीसी, (2018) 9 एससीसी 266: (2018) 4 एससीसी (सीआईवी) 351, , एससीसी पीपी 291–92, पैरा 25)

''25। ... इसके अलावा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

में खंड के विपरीत। [टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अ. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (2012) 12 एससीसी 10 : (2013) 2 एससीसी (सीआईवी) 122, , खंड 16 में ऐसी भाषा शामिल नहीं है जो प्रकृति में इतनी व्यापक है कि यह मध्यस्थ को पेंडेंट लाइट ब्याज देने से रोक देगा। यह याद रखा जाएगा कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में

खंड। [टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अ. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड , (2012) 12 एससीसी 10 : (2013) 2 एससीसी

(सीआईवी) 122, पार्टियों के बीच विवादों, मतभेदों या गलतफहमी के कारण सरकार के पास पड़े किसी भी धन के संबंध में ब्याज के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जा रहा है या देय नहीं किया जा सकता है, न कि केवल देरी या चूक के संबंध मेंय इसके अलावा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में खंड। लिमिटेड। खटिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अ. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड , (2012) 12 एससीसी 10 : (2013) 2 एससीसी (सीआईवी) 122, बहुत आगे जाता है और यह स्पष्ट करता है कि ब्याज के लिए कोई दावा ''किसी भी अन्य संबंध में'' देय नहीं है।''

यह उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त निर्णय में हरीश चंद्र मामले [उत्तर प्रदेश राज्य, पर भी चर्चा और विश्लेषण किया गया है। अ. हरीश चंद्र एंड कंपनी। , (1999) 1 एससीसी 63, । सबसे पहले, हरीश चंद्र 45 में फेसला मामला [उत्तर प्रदेश राज्य, अ. हरीश चंद्र एंड कंपनी। (1999) 1 एससीसी 63, 1940 के अधिनियम के अंतर्गत है। इससे भी अधिक प्रासंगिक बात यह है कि इस फैसले को सईद अहमद एंड कंपनी मामले [सईद अहमद एंड कंपनी, में समझाया और प्रतिष्ठित किया गया है। अ. उत्तर प्रदेश राज्य , (2009) 12 एससीसी 26: (2009) 4 एससीसी (सीआईवी) 629, निम्नलिखित पैराग्राफ में: (सईद अहमद एंड कंपनी केस [सईद अहमद एंड कंपनी। अ. उत्तर प्रदेश राज्य , (2009) 12 एससीसी 26: (2009) 4 एससीसी (सीआईवी) 629, , एससीसी पीपी 33–34, पैरा 17–19) ''17। अपीलकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया। अ. हरीश चंद्र एंड कंपनी। [उत्तर प्रदेश राज्य, अ. हरीश चंद्र एंड कंपनी। (1999) 1 एससीसी 63, यह तर्क देने के लिए कि अनुबंध के खंड 1.09 ने ब्याज देने पर रोक नहीं लगाई। उस निर्णय में विचार के लिए आने वाले ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड निम्नानुसार था: (एससीसी पृष्ठ 67, पैरा 9) '1.09। विवाद आदि के कारण देरी से भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा – सरकार द्वारा किसी भी पैसे या शेष राशि के संबंध में ब्याज या क्षति के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा जो किसी भी विवाद, अंतर के कारण सरकार के पास पड़ा होय या समय–समय पर या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता के बीच गलतफहमी या किसी अन्य संबंध में। इस न्यायालय ने कहा कि उक्त खंड नुकसान के किसी भी दावे पर ब्याज देने या

किए गए कार्य के लिए भुगतान के दावे पर रोक नहीं लगाता है। हम इस तरह के निर्णय के लिए तर्क नीचे निकालते हैंः (हरीश चंद्र [उत्तर प्रदेश राज्य, अ. हरीश चंद्र एंड कंपनी। , (1999) 1 एससीसी 63, , एससीसी पी. 67, पैरा 10) '10. खंड पर केवल एक नजर डालने से पता चलता है कि क्षतिपूर्ति के माध्यम से ब्याज के दावे पर सरकार के विरुद्ध केवल एक निर्दिष्ट प्रकार की राशि अर्थात् कोई धनराशि या शेष राशि जो किसी विवाद के कारण सरकार के पास पड़ी हो सकती है, प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच अंतर के संबंध में विचार नहीं किया जाना थाय या समय–समय पर या अंतिम भुगतान करने में या किसी अन्य संबंध में प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच गलतफहमी। शब्द ''या किसी अन्य संबंध में'' भी 46 यह उन धनों या शेष राशियों से संबंधित विवाद से संबंधित है जो समझौते के अनुसरण में सरकार के पास पड़े हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि प्रतिभूति जमा या प्रतिधारण धन या कोई अन्य राशि जो सरकार के पास हो सकती है और जिसकी वापसी सरकार द्वारा रोक दी गई हो सकती है। नुकसान का दावा या किए गए काम के लिए भुगतान का दावा और जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से किसी भी धन को कवर नहीं करेगा जिसे सरकार के पास पड़ा हुआ कहा जा सकता है। नतीजतन, इस खंड की स्पष्ट भाषा में, ऐसा कोई निषेध नहीं है जिसे प्रतिवादी ठेकेदार के खिलाफ मारा जा सकता है कि वह निर्णय के लिए रखी गई प्रासंगिक वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष नुकसान के रूप में ब्याज के लिए दावा नहीं उठा सकता है।

18. हरीश चंद्र [उत्तर प्रदेश राज्य, अ. हरीश चंद्र एंड कंपनी। (1999) 1 एससीसी 63, खंड 1.09 के एक अलग संस्करण पर विचार किया गया था। उस खंड के प्रतिबंधात्मक शब्दों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि यह नुकसान के दावे या किए गए काम के लिए भुगतान के दावे पर ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है और जिसका भुगतान नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने कहा कि उक्त खंड केवल उन राशियों पर ब्याज देने से

रोकता है जो सरकार के पास जमानत जमा/प्रतिधारण राशि या किसी अन्य राशि के माध्यम से पड़ी हो सकती हैं, जिसकी वापसी सरकार द्वारा रोक दी गई थी।

19. लेकिन वर्तमान मामले में, खंड जी 1.09 काफी अलग है। इसमें विशेष रूप से प्रावधान है कि प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच किसी विवाद, अंतर या गलतफहमी के कारण या प्रभारी अभियंता की ओर से आवधिक या अंतिम भुगतान करने में या किसी अन्य संबंध के संबंध में किसी भी देरी के संबंध में किसी भी धन के संबंध में कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस मामले में खंड जी 1.09 के तहत बार पूर्ण होने के कारण, हरीश 47 में

निर्णय चंद्रा [उत्तर प्रदेश राज्य, अ. हरीश चंद्र एंड कंपनी। (1999) 1 एससीसी 63, अपीलकर्ता की किसी भी तरह से सहायता नहीं करेगा।

67. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (उक्त) के मामले में वर्ष 2012 और 2019 दोनों में और हरीश चंद (उक्त) और सईद अहमद (उक्त) के मामले में किए गए ब्याज के सवाल पर चर्चा से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ब्याज का भुगतान हमेशा अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के अधीन रहा है।

68. इस मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उस समय उपलब्ध कानून के अनुसार अनुबंध की शर्तों की व्याख्या की [(हरीश चंद (उक्त) ,। यह सच है कि एक निर्णय जो कानून की व्याख्या करता है, सभी कार्यवाही पर लागू होता है।

69. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (उक्त) 2012 और 2019 दोनों के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। अधिनियम की धारा 31 (7) के तहत सन्निहित ब्याज के भुगतान के संबंध में कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है। इन दो मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक संविदा के खंड की व्याख्या की और 48 एक दृष्टिकोण लिया। दरअसल, साल 2019 के जय प्रकाश एसोसिएट्स (उक्त) के मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी विचार–विमर्श किया गया है. एक अन्य संभावित दृष्टिकोण था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

70. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि वर्ष 2012 और 2019 दोनों के जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (उक्त) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए खंडों की व्याख्या का मध्यस्थ अधिनिर्णय को स्पष्ट रूप से अवैध बनाने के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध के खंड के उल्लंघन में रुचि दी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध के खंड की व्याख्या की और ब्याज पर निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, एक न्यायिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। हरीश चंद (उक्त) के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर विचार किया गया है।

71. यह स्थिति एसोसिएट बिल्डर्स (उक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की उक्ति द्वारा कवर की गई है। पेटेंट अवैधता के सवाल पर जब यह 49 के आधार पर आधारित है अनुबंध की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस उल्लंघन को एक चेतावनी के साथ समझा जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई मध्यस्थ उचित तरीके से अनुबंध की अवधि का अर्थ लगाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस आधार पर निर्णय को रद्द किया जा सकता है।

72. एसोसिएट बिल्डर्स (उक्त) के मामले में फैसले के पैरा 42.3 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह देखा गया है, जिसे पहले ही उद्धृत किया जा चुका है, लेकिन पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह न्यायालय इसे एक बार फिर से पुनः पेश करता है। यह निम्नानुसार है –

> ''एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई मध्यस्थ उचित तरीके से अनुबंध की अवधि का अर्थ लगाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस आधार पर निर्णय को रद्द किया जा सकता है। अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करना है जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं मानता है कि इसे कुछ

ऐसा कहा जा सकता है जो कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं कर सकता है।

73. इस मामले में भी, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने वर्ष 2007 में अनुबंध की अवधि का अर्थ निकाला और एक विचार लिया। यह एक संभावित दृष्टिकोण है। इसके बाद, वर्ष 2012 में और उसके बाद वर्ष 2019 में, अनुबंध की समान शर्तों को 50 आयोजित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ब्याज के भुगतान पर रोक लगा दी गई है, लेकिन यह मध्यस्थ निर्णय को स्पष्ट रूप से अवैध नहीं बनाता है। 74. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को अपील में कोई दम नजर नहीं आता है। तदनुसार, अपील खारिज की जा सकती है।

74. अपील खारिज की जाती है ।

(रवींद्र मैथानी, जे.)

05.01.2022

अवनीत **********